पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की बैठक सम्पन्न

एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित सड़कों के निर्माण तथा गंगा की धारा को निर्मल व अविरल बनाने के कार्यक्रमों में राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी

विकास गतिविधियों एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दूर–दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कें आवश्यक

राज्य सरकार को एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने के लिए 200 करोड़ रु0 की धनराशि मिलेगी

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित किया

उत्तर प्रदेश में एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित 2000 कि0मी0 सड़कों का निर्माण और किया जाएगा : श्री नितिन गडकरी

लखनऊ : 25 जनवरी, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित सड़कों के निर्माण तथा गंगा की धारा को निर्मल व अविरल बनाने के कार्यक्रमों में पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि विकास गतिविधियों एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दूर–दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कें आवश्यक हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार मजबूत और टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए कृतसंकल्पित है।

मुख्यमंत्री जी आज शास्त्री भवन में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने श्री गडकरी का स्वागत करते हुए प्रदेश के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर श्री गडकरी को प्रतीक चिन्ह् के रूप में 'कुम्भ का लोगो' भेंट किया।

योगी जी ने कहा कि नई तकनीक और विकास परियोजनाओं में शीघ्रता लाकर प्रगति और समृद्धि हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रकरणों को शीघ्रता से हल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों के लिए बालू, मौरंग और मिट्टी की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। बैठक में एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित सड़कों को

गड्ढामुक्त किए जाने के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से अनुरोध किया गया। इसके लिए श्री गडकरी ने 200 करोड़ रुपए की धनराशि दिए जाने की बात कही।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रशासकीय शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 03 प्रतिशत कर दिया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा यूटीलिटी शिफ्टिंग के लिए 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज को घटाकर 05 प्रतिशत कर दिया गया है। सिंचाई एवं जल विभाग के स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा मिट्टी खनन के लिए अनुमति प्रदान किए जाने के नियम में संशोधन करते हुए एन0एच0ए0आई0 की अपेक्षानुसार सरलीकृत कर दिया गया है और सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है।

समस्त मण्डलायुक्तों को एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित व्यवधानों के निस्तारण के लिए मॉनीटरिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और प्रतिमाह समीक्षा बैठक में इस सम्बन्ध में अनुश्रवण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। एन0एच0ए0आई0 को बालू खनन हेतु पट्टा आवंटित किया गया है तथा आवश्यक क्लीयरेन्स भी निर्गत हो गई है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर0पी0 सिंह, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी सहित अन्य विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव एवं केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के पश्चात् मीडिया सेण्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी सम्मिलित हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का हर सम्भव सहयोग मिल रहा है।

श्री गडकरी ने कहा कि केन–बेतवा योजना के सम्बन्ध में भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहमति हो चुकी है, जिसका शीघ्र ही एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें केन्द्र सरकार 28 हजार करोड़ रुपए का योगदान कर रही है और यह देश की पहली नदी जोड़ो योजना होगी। यह योजना साढ़े तीन वर्षों

में पूरी होने की सम्भावना है, जिससे 12 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में विकास की तस्वीर बदलेगी।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने बताया कि वाराणसी से हल्दिया के बीच इन्लैण्ड वाटर वेज का भी कार्य किया जा रहा है और इसमें हल्दिया, वाराणसी तथा साहिबगंज के अलावा, गाजीपुर को भी हब के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जल परिवहन, सड़कों और रेलवे के मुकाबले सस्ता पड़ता है। यह मार्ग पर्यटन और परिवहन की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। सी–प्लेन का भी उपयोग बढ़ाए जाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित 55 में से 35 के डी0पी0आर0 प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एन0एच0ए0आई0 से सम्बन्धित 2000 कि0मी0 सड़कों का निर्माण और किया जाएगा।

श्री गडकरी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रकरणों के समाधान के लिए राज्य सरकार शीघ्रता से कार्यवाही कर रही है। गंगा नदी पर फाफामऊ में एक और ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए आएगी। इसके साथ ही, गंगा नदी पर वाराणसी से इलाहाबाद के बीच में भी जल परिवहन का आरम्भ कुम्भ–2019 के पहले किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। कुम्भ के मद्देनजर इलाहाबाद में अन्य विकास परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। गंगा नदी की धारा को निर्मल व अविरल बनाने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का दूषित जल गंगा नदी में न आए। इसके लिए वॉटर री–साइकिलिंग के प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जा रहा है। गंगा किनारे के साढ़े चार हजार गांवों को विकसित करने के भी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंगा हमारे देश की अस्मिता है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि दिल्ली से मेरठ के बीच में एक्सप्रेस हाईवे के बन जाने से 3 घण्टों का सफर 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। इसी प्रकार कानपुर से लखनऊ के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

———————

PN-CM-Meeting & PC-Union Transport Minister-25 January, 2018